SAARTHI · सारथी

करियर मार्गदर्शन पोर्टल · Career Guidance Portal

"सही मार्गदर्शन, उज्ज्वल भविष्य।"

करियर शीट · CAREER SHEET

Human Rights Lawyer

मानवाधिकार वकील उन लोगों और समूहों के लिए लड़ता है जिन्हें भारत के संविधान से गारंटीशुदा बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित रखा गया है। वह नागरिक स्वतंत्रता (जैसे बोलने, आस्था और सम्मान से जीने का अधिकार), महिलाओं, बच्चों,...

इस करियर की पूरी जानकारी — स्कैन करें

वेतन, परीक्षा, कॉलेज, प्रवेश के रास्ते और आगे के कदम — सब पोर्टल पर।

career.gsssjethantri.in/#/career/human-rights-lawyer

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जेठन्तरी

Govt. Sr. Sec. School, Jethantri · ब्लॉक समदड़ी · बालोतरा (Block Samdari · Balotra)

www.gsssjethantri.in · career.gsssjethantri.in

सुशील कुमार शर्मा
प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. जेठन्तरी · मास्टर ट्रेनर
Principal, GSSS Jethantri · Master Trainer

श्री चेनाराम चौधरी
प्रधानाचार्य, डाइट बाड़मेर
Principal, DIET Barmer

श्रीमती संघमित्रा
वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट बाड़मेर (सहयोग)
Sr. Lecturer, DIET Barmer (Support)

भरत चौधरी
अभिकल्पना व विकास · व्याख्याता (इतिहास)
Designed & developed · Lecturer (History)

विशेष धन्यवाद · SPECIAL THANKS

सुरेन्द्र सिंह राठौड़
व्याख्याता (इतिहास) · रा.उ.मा.वि. कानाना

सुरेश कुमार सैन
व्याख्याता (भूगोल) · रा.उ.मा.वि. रामसीन मूंगड़ा

वनिता कुमारी
व्याख्याता (इतिहास) · रा.उ.मा.वि. रामसीन मूंगड़ा

कमलेश चौधरी
व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) · रा.उ.मा.वि. टापरा

करियर मार्गदर्शन कार्यशाला, डाइट बाड़मेर (14–17 जुलाई 2026) में विकसित व लोकार्पित
Developed & unveiled at the Career Guidance Workshop, DIET Barmer (14–17 July 2026)

यह एक स्वतंत्र परियोजना है, जो सरकार की आधिकारिक करियर-मार्गदर्शन सामग्री पर आधारित है। · An independent project based on the Government's official career-guidance content.

1 यह करियर क्या है

मानवाधिकार वकील उन लोगों और समूहों के लिए लड़ता है जिन्हें भारत के संविधान से गारंटीशुदा बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित रखा गया है। वह नागरिक स्वतंत्रता (जैसे बोलने, आस्था और सम्मान से जीने का अधिकार), महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों, LGBTQ समुदाय, जातीय व धार्मिक अल्पसंख्यकों और गरीब-वंचित तबकों के हक की रक्षा करता है। वह अदालतों में जनहित याचिका (PIL) दायर करता है, पीड़ितों को मुफ़्त कानूनी सहायता देता है, मानवाधिकार आयोगों के सामने मामले रखता है और नीतियों में बदलाव के लिए काम करता है। यह करियर कमाई से ज़्यादा उद्देश्य और सामाजिक न्याय से जुड़ा है, और इसमें कानून की गहरी समझ के साथ मज़बूत ज़मीर की ज़रूरत होती है।

2 एक नज़र में

न्यूनतम योग्यता	12वीं के बाद 5-वर्षीय LLB या ग्रेजुएशन के बाद 3-वर्षीय LLB
प्रवेश परीक्षा	CLAT (NLU में प्रवेश हेतु)
आरंभिक वेतन	₹15,000–30,000/माह (NGO/जूनियर स्तर)
कार्य-शैली	अदालत, NGO, मानवाधिकार आयोग व कानूनी सहायता में पूर्णकालिक

3 क्या-क्या चाहिए

रुचियाँ

- न्याय, समानता और वंचितों के अधिकारों के प्रति गहरी रुचि
- कानून, संविधान और सामाजिक मुद्दों को पढ़ने-समझने का शौक
- बहस, तर्क और लोगों की समस्याओं को सुलझाने में रुचि

क्षमताएँ

- तार्किक सोच और मज़बूत विश्लेषण क्षमता
- प्रभावी लेखन और सार्वजनिक रूप से बोलने का कौशल
- धैर्य, सहानुभूति और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस

ज़रूरी कौशल

- संविधान, मानवाधिकार कानून और अदालती प्रक्रिया की गहरी समझ
- जनहित याचिका (PIL), याचिका व कानूनी दस्तावेज़ तैयार करना

- अदालत में बहस, दलील और मौखिक प्रस्तुति (advocacy)
- पीड़ितों की काउंसलिंग और संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत
- कानूनी शोध, केस लॉ और साक्ष्य का विश्लेषण
- अंग्रेज़ी व स्थानीय भाषा में स्पष्ट लेखन और संवाद

4 कैसे पहुँचें

1. 12वीं (किसी भी संकाय) अच्छे अंकों से पास करें और CLAT जैसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी करें।
2. CLAT के ज़रिए किसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (जैसे NLU जोधपुर) में 5-वर्षीय BA-LLB/BBA-LLB में प्रवेश लें; या ग्रेजुएशन के बाद 3-वर्षीय LLB करें।
3. पढ़ाई के दौरान मानवाधिकार, संवैधानिक कानून और आपराधिक कानून के विषय व मूट कोर्ट में भाग लें।
4. बार काउंसिल ऑफ इंडिया की AIBE परीक्षा पास कर अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराएं।
5. किसी मानवाधिकार वकील, NGO, कानूनी सहायता केंद्र (NALSA/DLSA) या मानवाधिकार आयोग के साथ इंटर्नशिप व अनुभव लें।
6. चाहें तो मानवाधिकार में LLM या विशेष कोर्स कर अपनी विशेषज्ञता बढ़ाएं।

प्रमुख परीक्षाएँ

- CLAT (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) — NLU में लॉ प्रवेश हेतु
- AIBE (अखिल भारतीय बार परीक्षा) — वकालत का लाइसेंस पाने हेतु

5 कहाँ से पढ़ें

सरकारी संस्थान

- राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (NLU Jodhpur) — जोधपुर, राजस्थान (https://www.nlujodhpur.ac.in/)
- राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली (NLU Delhi) — नई दिल्ली (https://nludelhi.ac.in/)
- नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) — बेंगलुरु, कर्नाटक (https://www.nls.ac.in/)

निजी संस्थान

- जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी — स्कूल ऑफ लॉ — जयपुर, राजस्थान (https://www.jnujaipur.ac.in/)
- सिम्बायोसिस लॉ स्कूल — पुणे, महाराष्ट्र (https://www.symlaw.ac.in/)

ऑनलाइन

- IGNOU — मानवाधिकार में सर्टिफिकेट कोर्स — ऑनलाइन / दूरस्थ शिक्षा (https://www.ignou.ac.in/)
- कॉन्सोर्टियम ऑफ NLUs — CLAT आधिकारिक पोर्टल — ऑनलाइन

फ़ीस

सरकारी NLU (जैसे NLU जोधपुर) में 5-वर्षीय लॉ कोर्स की फीस लगभग ₹2.5–3.5 लाख प्रति वर्ष होती है, जबकि राज्य के सरकारी लॉ कॉलेजों में यह बहुत कम (कुछ हज़ार रुपये प्रति वर्ष) हो सकती है। निजी विधि संस्थानों में फीस ₹1.5–5 लाख प्रति वर्ष तक जाती है। SC/ST/OBC व आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और फीस माफ़ी उपलब्ध है।

छात्रवृत्तियाँ

- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) (https://scholarships.gov.in/)
- SJE राजस्थान छात्रवृत्ति (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) (https://sje.rajasthan.gov.in/)
- Buddy4Study — लॉ स्कॉलरशिप्स (https://www.buddy4study.com/scholarships/law-scholarships)

6 काम कैसा होता है

कहाँ काम

जिला व उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, मानवाधिकार NGO व कानूनी सहायता संस्थाएं, राष्ट्रीय/राज्य मानवाधिकार आयोग, विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA/DLSA) और संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं।

कार्य-संस्कृति

काम में लंबे और अनियमित घंटे, केस की तैयारी, फील्ड विज़िट और अदालती सुनवाई शामिल है। यह भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण पर बेहद संतोषजनक क्षेत्र है, जहाँ अक्सर सीमित संसाधनों में समाज के सबसे कमज़ोर लोगों के लिए काम करना पड़ता है।

कौन नौकरी देता है

- मानवाधिकार NGO व कानूनी सहायता संगठन (जैसे ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, लॉयर्स कलेक्टिव)
- राष्ट्रीय व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA/RSLSA/DLSA)
- संयुक्त राष्ट्र व अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं
- राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग
- स्वतंत्र वकालत — जनहित याचिका व संवैधानिक मामलों की प्रैक्टिस
- विश्वविद्यालय, विधि संस्थान व नीति अनुसंधान संगठन (शिक्षण/शोध)

माँग (2026)

बढ़ती सामाजिक जागरूकता, संवैधानिक अधिकारों को लेकर सक्रियता और जनहित याचिकाओं की संख्या के कारण मानवाधिकार वकीलों की माँग बनी हुई है। नियमित, अच्छी कमाई वाले पद NGO व अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सीमित हैं, इसलिए यह क्षेत्र उन युवाओं के लिए है जो न्याय व समाज-सेवा को प्राथमिकता देते हैं। अनुभवी व प्रतिष्ठित वकील अदालती प्रैक्टिस से स्थिर पहचान और आय दोनों बना लेते हैं।

7 आगे बढ़ने का रास्ता

1. लॉ इंटर्न / जूनियर एडवोकेट
2. मानवाधिकार वकील (NGO/स्वतंत्र प्रैक्टिस)
3. वरिष्ठ अधिवक्ता / कानूनी सलाहकार / कार्यक्रम प्रमुख
4. वरिष्ठ अधिवक्ता (सुप्रीम कोर्ट), मानवाधिकार आयोग सदस्य या न्यायाधीश

कमाई

शुरुआत	₹15,000–30,000/माह
मध्य स्तर	₹40,000–75,000/माह
वरिष्ठ स्तर	₹1,00,000–2,50,000+/माह

मानवाधिकार वकालत मुख्यतः उद्देश्य-प्रेरित क्षेत्र है, इसलिए शुरुआती व NGO स्तर की आय अक्सर मामूली रहती है। कॉर्पोरेट वकालत की तुलना में कमाई कम होती है, पर अनुभव, प्रतिष्ठा और सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता बनने पर आय काफी बढ़ जाती है। कई वकील मुफ़्त (प्रो-बोनो) मामले भी लेते हैं। आँकड़े अनुमानित हैं और शहर, संस्था व अनुभव के अनुसार बदलते हैं।

8 अच्छी बातें · चुनौतियाँ

अच्छी बातें

- समाज के सबसे कमज़ोर लोगों के लिए सीधे बदलाव लाने का मौका
- गहरा उद्देश्य, सम्मान और सामाजिक न्याय की संतुष्टि
- संविधान व कानून की मज़बूत समझ, जो कई करियर रास्ते खोलती है

चुनौतियाँ

- कॉर्पोरेट वकालत की तुलना में आय अक्सर कम और अनिश्चित
- भावनात्मक रूप से थका देने वाले मामले और लंबी अदालती लड़ाइयाँ
- कभी-कभी दबाव, विरोध और सीमित संसाधनों में काम करना पड़ता है

9 असल ज़िंदगी की कहानियाँ

Colin Gonsalves
वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट; ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क (HRLN) के संस्थापक

आईआईटी बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग करने वाले कॉलिन गोंसाल्वेस ने बाद में नाइट स्कूल से कानून की पढ़ाई कर वकील बनने का रास्ता चुना। उन्होंने 1989 में ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क (HRLN) की स्थापना की, जो आज 200 से अधिक वकीलों व कार्यकर्ताओं के साथ भारत का प्रमुख जनहित कानून समूह है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में उन्होंने भोजन के अधिकार, बाल श्रम, मज़दूरों के स्वास्थ्य और तेज़ाब हमले पीड़ितों के मुआवज़े जैसे कई ऐतिहासिक मामले जीते। तीन दशकों तक जनहित याचिका के ज़रिए वंचितों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें 2017 में प्रतिष्ठित 'राइट लाइवलीहुड अवार्ड' (वैकल्पिक नोबेल) से सम्मानित किया गया।

Wikipedia · https://en.wikipedia.org/wiki/Colin_Gonsalves

Indira Jaising
वरिष्ठ अधिवक्ता; भारत की पहली महिला अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल

इंदिरा जयसिंह 1986 में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता नामित होने वाली पहली महिला बनीं और 2009 में भारत की पहली महिला अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बनीं। उन्होंने 1981 में 'लॉयर्स कलेक्टिव' की सह-स्थापना की और महिलाओं, अल्पसंख्यकों व वंचितों के मानवाधिकारों के लिए दशकों तक लड़ाई लड़ी। मैरी रॉय मामले में उन्होंने ईसाई महिलाओं को समान संपत्ति अधिकार दिलाए, तो गीता हरिहरन मामले में माँ को पिता के समान संरक्षक का दर्जा। उन्हें 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2018 में फॉर्च्यून पत्रिका की '50 महानतम नेताओं' की सूची में जगह मिली। उनका सफ़र दिखाता है कि कानून को सामाजिक न्याय का औज़ार बनाया जा सकता है।

Wikipedia · https://en.wikipedia.org/wiki/Indira_Jaising

10 अगर यह रास्ता न बने तो

एक परीक्षा या एक प्रयास से रास्ता बंद नहीं होता। इन्हीं विषयों से ये रास्ते भी खुलते हैं — इनमें प्रवेश आमतौर पर आसान होता है और आगे चलकर इसी क्षेत्र में लौटा जा सकता है।

- न्यायाधीश
- मध्यस्थ / विवाचक (आर्बिट्रेटर)
- कॉर्पोरेट कानूनी सलाहकार / अनुपालन अधिकारी

11 स्रोत व आगे पढ़ें

1. राजस्थान करियर गाइडेंस — मानवाधिकार वकील — https://cg.rajasthan.gov.in/careerguidance/hi/career/%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a7%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%b5%e0%a4%95%e0%a5%80%e0%a4%b2/

2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) — https://nhrc.nic.in/

3. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) — https://nalsa.gov.in/

4. करियर्स360 — ह्यूमन राइट्स लॉयर — https://www.careers360.com/careers/human-rights-lawyer

और 770+ करियर — पूरा पोर्टल

रुचि व योग्यता परीक्षण, सरकारी नौकरियाँ, कौशल पाठ्यक्रम, बायोडाटा बनाने की सुविधा — सब मुफ़्त, बिना लॉगिन, इंटरनेट के बिना भी।

career.gsssjethantri.in